

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राज्य स्तरीय अमृता हाट : जयपुर
2.	राजस्थान फिल्म फेस्टिवल (RFF) - 2025
3.	इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज : 'अमोघ फ्यूरी'
4.	निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में संशोधन
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा 2. बाजरा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क : गुड़ामालानी 3. धनंजय सिंह खींवसर 4. अन्वी राठौड़ और जंगजीत सिंह काजला 5. कृष्णा नागर 6. 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर : भिवाड़ी 7. नरेगा आखर अभियान : जयपुर 8. 'जीएसटी बचत उत्सव' 9. रिया कंवर शेखावत 10. जोधपुर IIT की 'मातृभाषा हिंदी मॉडल' पहल
6.	त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी कार्यशाला (T-सैट्स)
7.	ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, 2025
8.	संयुक्त राष्ट्र : संरचनात्मक सुधारों पर प्रगति रिपोर्ट, 2025
9.	सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता
10.	चाबहार बंदरगाह
11.	हाई सीज ट्रीटी (खुले समुद्र पर संधि)

--:1:--

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



12.	H-1B वीजा
13.	मेक इन इंडिया को दशक पूर्ण
14.	प्रोजेक्ट स्वायत्त
15.	ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
16.	इंडिया AI मिशन
17.	भारत का लॉजिस्टिक्स लागत तंत्र
18.	भारत और ग्रीस के मध्य पहला द्विपक्षीय अभ्यास
19.	दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2023



--:2:--



राजस्थान परिदृश्य



राज्य स्तरीय अमृता हाट : जयपुर



चर्चा में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार द्वारा 21 सितंबर, 2025 को जवाहर कला केंद्र, जयपुर में आयोजित 'राज्य स्तरीय अमृता हाट' का उद्घाटन किया गया।


सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान

राज्य स्तरीय अमृता हाट

रविवार, 21 - 30 सितम्बर 2025
प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक

स्थान :
दक्षिण परिसर,
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित है।

 निदेशालय महिला अधिकारिता
जयपुर


Amrita
A self help group initiative

--:3:--



मुख्य बिन्दु:

- **आयोजक** : निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
- **आयोजन** : 21 से 30 सितम्बर, 2025 तक।
- **उद्देश्य** : महिला उद्यमियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रतिभा को मंच प्रदान कर उन्हें आर्थिक सशक्तीकरण की मुख्यधारा से जोड़ना।
- अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है, जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है।
- राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF), शिल्प ग्राम उत्सव तथा अन्य विभागीय मेलों जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) या राजीविका

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) या राजीविका की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- यह राजस्थान सोसायटी अधिनियम - 1958 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।
- **अध्यक्ष** : मुख्यमंत्री।
- **उद्देश्य**: ग्रामीण विकास के लिए की जा रही सरकारी और गैर-सरकारी पहलों के बीच प्रभावी अभिसरण लाना।
- स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों, सामुदायिक विकास संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के गठन और सुदृढीकरण में सहायता करना।
- गरीबों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना।

राजस्थान फिल्म फेस्टिवल (RFF) - 2025

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, दीप स्मृति ऑडिटोरियम, मानसरोवर (जयपुर) में 'राजस्थान फिल्म फेस्टिवल (RFF) - 2025' का आयोजन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- आयोजक :** कंचन कैसेट्स एंड सीरीज (के-सीरीज) की एक पहल। प्रति वर्ष जयपुर में आयोजन।

राजस्थानी फिल्मों की श्रेणी में पुरस्कार:

- सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म :** हुकूम।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक :** पंकज सिंह तंवर (फिल्म - हुकूम)
- सर्वश्रेष्ठ लेखक :** डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी (रचना - भरखमा)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता :** श्रवण सागर कल्याण (भरखमा के लिए)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री :** सुष्मिता राणा (सपना एक उड़ान)
- सर्वश्रेष्ठ गीतकार :** जी. नटराज (बैरण फिल्म के गीत "बेटी तू क्यों जाई..." के लिए)

इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज : 'अमोघ फ्यूरी'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज 'अमोघ फ्यूरी' का आयोजन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजक** : बीकानेर सेना की सप्त शक्ति कमान।
- इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक समय के युद्ध परिदृश्यों में युद्ध शक्ति, समन्वय और परिचालन तत्परता का परीक्षण करना था, जो बहु-क्षेत्रीय अभियानों के लिए सेना की तैयारी को दर्शाता है।
- 'अमोघ फ्यूरी' का मुख्य फोकस आधुनिक तकनीकों का एकीकरण था, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित संचार, कमांड-एंड-कंट्रोल आर्किटेक्चर, और वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणालियाँ शामिल हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान में सम्पन्न अन्य सैन्य अभ्यास:

- एक्सरसाइज डेजर्ट हंट** : भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से वायु सेना स्टेशन जोधपुर में 24 से 28 फरवरी, 2025 तक।
- एक्सरसाइज बोल्ट कुरूक्षेत्र** : भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जोधपुर में 28 जुलाई से 4 अगस्त, 2025 तक।

निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद' द्वारा 'निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना' में संशोधन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- संशोधन के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा 8वीं कक्षा तक के सामान्य और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्व में प्रदान की जाने वाली यूनिफॉर्म की राशि को बंद कर दिया गया है।
- साथ ही, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 12 लाख बालिकाओं को भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है।
- नए प्रावधानों के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक की सभी बालिकाओं और SC-ST व BPL के बालकों को यूनिफॉर्म की राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
- **राशि** : पहली से आठवीं कक्षा तक की समस्त बालिकाओं और एससी, एसटी व बीपीएल के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600 प्राप्त होंगे।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा</p> <ul style="list-style-type: none">केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जोधपुर के रामराज नगर चौखा में 'श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय' के नवीन भवन का उद्घाटन किया।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा नेत्रहीन विकास संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष सुशीला बोहरा की जीवनी 'मैं न थकी न हारी' पुस्तक के ब्रेल लिपी संस्करण का विमोचन किया गया।
2.	<p>बाजरा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क : गुड़ामालानी</p> <ul style="list-style-type: none">केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने 21 सितंबर, 2025 को बाड़मेर के गुड़ामालानी में 'बाजरा अनुसंधान केंद्र' में 'बाजरा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क' का शिलान्यास किया।
3.	<p>धनंजय सिंह खींवसर</p> <ul style="list-style-type: none">28 सितंबर, 2025 को मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की वार्षिक साधारण सभा (AGM) में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) का प्रतिनिधित्व RCA की एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर द्वारा किया जाएगा।ज्ञातव्य है कि इस बैठक में BCCI के अध्यक्ष और IPL के चेयरमैन सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव होंगे।

4.

अन्वी राठौड़ और जंगजीत सिंह काजला

- राजस्थान की अन्वी राठौड़ (U-15 गर्ल्स) और जंगजीत सिंह काजला (U-17 डबल्स) का चीन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ।
- अन्वी और जंगजीत सिंह ने पंचकुला में आयोजित योनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई।

5.

कृष्णा नागर

- राजस्थान के पैरा शटलर कृष्णा नागर ने हाल ही में चीन में आयोजित 'पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट' में रजत पदक जीता।
- टोक्यो पैरालिंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर ने पुरुषों की SH6 स्पर्धा में यह पदक जीता।
- फाइनल मुकाबले में कृष्णा नागर थाइलैंड के नात्थापोंग मीचाई से पराजित हुए।

6.

12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर : भिवाड़ी

- 19 से 21 सितम्बर, 2025 तक खैरथल-तिजारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जिला प्रशासन खैरथल-तिजारा एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में भिवाड़ी में 12वाँ इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन किया गया।

7.

नरेगा आखर अभियान : जयपुर

- जयपुर जिला प्रशासन की पहल पर ग्रामीण विकास विभाग, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से जयपुर जिले में 'नरेगा आखर अभियान' का संचालन किया जा रहा है।
- इस अभियान के तहत 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)' के तहत कार्यरत निरक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाने का कार्य किया जा है।

8.

'जीएसटी बचत उत्सव'

- राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 22 से 29 सितम्बर, 2025 तक GST सुधार एवं दर युक्तिकरण जन-जागरूकता कार्यक्रम 'GST बचत उत्सव' का आयोजन किया जाएगा।
- इस अभियान का उद्देश्य GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना है।
- वन नेशन वन टैक्स प्रणाली की ओर बढ़ते हुए देश में 01 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था।
- इसमें 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत की चार अलग-अलग टैक्स स्लैब थी लेकिन दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से देश भर में मुख्य रूप से दो दरें 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत प्रभावी है।

9.

रिया कंवर शेखावत

- कोटा में आयोजित राजस्थान पावरलिफ्टिंग संघ की ओर से 30वीं स्टेट बेंच प्रेस प्रतियोगिता में जयपुर की रिया कंवर शेखावत ने सब जूनियर कैटेगरी की 76 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता।
- रिया ने 90 किलो बेंच प्रेस में यह पदक जीता।

10.

जोधपुर IIT की 'मातृभाषा हिंदी मॉडल' पहल

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), जोधपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत वर्ष 2024 से बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराने की सुविधा उपलब्ध कराई।
- देश के 23 IITs में से जोधपुर IIT यह पहल करने वाली देश की पहली संस्था है। इसे 'मातृभाषा हिंदी मॉडल' नाम दिया गया है।



राष्ट्रीय परिदृश्य



त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी कार्यशाला (T-सैट्स)

Defense & Military

Artificial
Intelligence

Immersive
Technologies

Advanced
Defense
Equipment

Additive
Manufacturing

Robotics
& Autonomous
Systems

Big Data
& Analytics

Internet of
Military Things

5G

Cyber Warfare

Blockchain

TOP MILITARY INNOVATIONS

-:11:-

मुख्य बिन्दु:

- **उद्घाटन** : 22 सितंबर, 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान द्वारा।
- **आयोजन** : 22 से 23 सितंबर, 2025 तक मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली।
- आधिकारिक संगोष्ठी पोर्टल (www.tsats.org.in) के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत 222 प्रतिक्रियाओं में से चुने गए नवाचारों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा।
- **आयोजक** : भारतीय सेना द्वारा मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।
- **इस प्रथम कार्यशाला का विषय** : "विवेक व अनुसंधान से विजय" - बुद्धि और नवाचार के माध्यम से विजय।
- **उद्देश्य** : राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सेवा-अकादमिक अनुसंधान एवं विकास इको सिस्टम में समंजस्य बनाना।
- सशस्त्र बलों और भारत के शैक्षणिक संस्थानों के मध्य नवाचार को बढ़ावा देने और सहयोग को मजबूत करना।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (CCC 2025) :

- **आयोजन** : सितंबर, 2025 को कोलकाता में आयोजित की गई।
- **उद्देश्य** : सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैयारियों, संयुक्त संचालन क्षमता एवं भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना।

चर्चा के मुख्य बिंदु:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा** : सीमाओं पर बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर विचार-विमर्शस्पेस, साइबर, इन्फॉर्मेशन वारफेयर और स्पेशल ऑपरेशंस जैसे नए डोमेन पर चर्चा की गई।

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



- **टेक्नोलॉजी-ड्रिवन एप्रोच** : आधुनिक युद्ध में AI, ड्रोन, साइबर डिफेंस का प्रयोग।
- **संस्थागत सुधार** : स्पेस, साइबर व इन्फॉर्मेशन डोमेन में संरचना सुधार।
- **प्रोक्योरमेंट सुधार** : पारदर्शिता व वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण।
- **ECHS की समीक्षा**: पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता।

परिणाम :

1. वायुसेना, थलसेना और नौसेना की शिक्षा शाखाओं को मिलाकर एक संयुक्त त्रि-सेवा शिक्षा कोर (Tri-Services Education Corps) बनाया जाएगा।
2. देश में तीन संयुक्त सैन्य स्टेशन (Joint Military Stations) स्थापित किए जाएंगे।
3. रिसर्च एंड डेवलपमेंट (DRDO, निजी कंपनियाँ आदि) में निवेश बढ़ाया जाएगा।
4. AI, बिग डेटा, क्वांटम टेक्नोलॉजी को रक्षा रणनीति में शामिल किया जाएगा।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:13:--

ई-गवर्नेंस पर 28वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन, 2025

चर्चा में क्यों?

- 22 सितंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।



The poster for the 28th National Conference on e-Governance features the following elements:

- Logos:** Department of Administrative Services & Public Services, Government of India; IIM; Nasscom.
- Central Text:** 28th National Conference on e-Governance, Novatel Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 22-23 September, 2025.
- Speakers:**
 - Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister
 - Shri N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister, Andhra Pradesh
 - Dr Jitendra Singh, Hon'ble Minister of State (In-charge) Science & Technology, Earth Sciences, MoS PMO, PFI, DoPT, Atomic Energy, Space
 - Shri Pawan Kalyan, Hon'ble Deputy Chief Minister, Andhra Pradesh
 - Shri Nara Lokesh, Hon'ble Minister for IT, Human Resources Development of Andhra Pradesh
- Theme:** Viksit Bharat: Civil Service and Digital Transformation

मुख्य बिन्दु:

- आयोजन :** 22 और 23 सितंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है।
- इस वर्ष के सम्मेलन का विषय :** 'विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन'।

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



- **आयोजक :** प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से।
- **संस्करण :** 28वाँ।
- **सम्मेलन का उद्देश्य :** भारत में सुरक्षित और टिकाऊ ई-सेवा वितरण सुनिश्चित करने हेतु नवीन और परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों पर चर्चा करने हेतु सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना; जिससे विकसित भारत के विज्ञान में योगदान दिया जा सके।
- **ई-गवर्नेंस में राष्ट्रीय पुरस्कार, 2025 :** सम्मेलन के दौरान, 19 अनुकरणीय पहलों को ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे।
- यह पुरस्कार, छह श्रेणियों (10 स्वर्ण, 6 रजत और 3 जूरी पुरस्कार)में केंद्र, राज्य, जिला प्राधिकरणों, ग्राम पंचायतों और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को प्रदान किए जाएँगे।
- ई-गवर्नेंस, 2025 पर विशाखापत्तनम घोषणापत्र पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की संयुक्त सचिव सरिता चौहान वक्तव्य देंगी।

सत्र :

- सम्मेलन में 6 पूर्ण सत्र और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। कुल मिलाकर, विविध पृष्ठभूमियों के लगभग 70 वक्ता अपने अनुभव साझा करेंगे और विभिन्न उप-विषयों पर सर्वोत्तम अभ्यास प्रस्तुत करेंगे, जैसे:
 1. विशाखापट्टनम: आईटी हब।
 2. विकसित भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता: समावेशी और मापनीय समाधानों का संचालन।
 3. सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन।
 4. ई-गवर्नेंस में साइबर सुरक्षा: विश्वास, बुनियादी ढाँचे और डिजिटल संप्रभुता की रक्षा।

--:15:--

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



5. सेवा वितरण की बेंचमार्किंग और उन्नति।
6. एग्री स्टैक - कृषि के लिए डिजिटल समाधान।
7. NAEG, 2025-I के स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं द्वारा ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता।
8. NAEG, 2025-II के स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं द्वारा ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता।
9. ई-गवर्नेंस में ग्राम पंचायत और जमीनी स्तर के नवाचार।
10. आंध्र प्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस पहल।
11. भारत के लिए नवाचार: ई-गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तिकरण में उत्प्रेरक।
12. अंतरराष्ट्रीय समुद्री ई-गवर्नेंस की रीढ़ के रूप में केबल और AI डेटा सेंटर।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:16:--

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र : संरचनात्मक सुधारों पर प्रगति रिपोर्ट, 2025

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'UN-80' पहल की तीसरी वर्कस्ट्रीम के तहत संरचनात्मक सुधारों और कार्यक्रम पुनर्गठन पर प्रगति रिपोर्ट का अनावरण किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित

मुख्यालय

- न्यूयॉर्क सिटी

पहला सत्र

- 17 जनवरी, 1946 को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन में

सदस्यता

- 15 सदस्य- 5 स्थायी सदस्य (P5), 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष 5 का चुनाव किया जाता है)
- P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन

UNSC की अध्यक्षता

- 15 सदस्यों के बीच प्रत्येक माह बारी-बारी से
- वर्ष 2022 के लिये भारत की अध्यक्षता-दिसंबर

मतदान शक्तियाँ

- 1 सदस्य = 1 मत/वोट
- P5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- UN के ऐसे सदस्य जो UNSC के सदस्य नहीं हैं, मतदान के अधिकार के बिना इसके सत्र में भाग लेते हैं

UNSC समितियाँ/प्रस्ताव

- आतंकवाद:
 - संकल्प 1373 (आतंकवाद रोधी समिति)
 - संकल्प 1267 (दाएश और अल कायदा समिति)
- अप्रसार समिति:
 - संकल्प 1540 (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)

भारत और UNSC

- गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22 में 8वीं बार चुना गया; स्थायी सीट की मांग
- स्थायी सीट के लिये तर्क:
 - 43 शांति मिशन
 - मानवाधिकार घोषणा (UDHR) को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
 - भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली आदि।

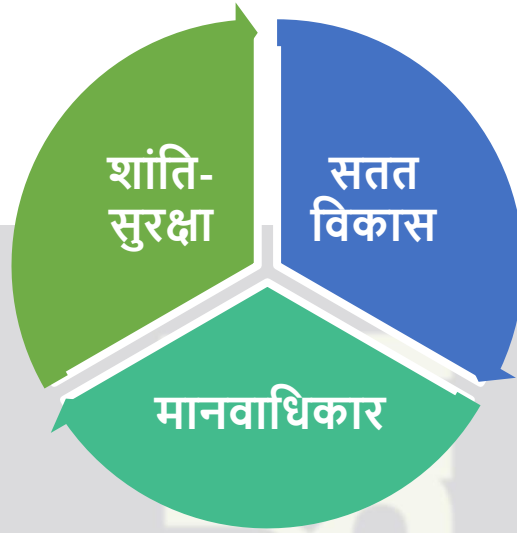
G4- चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं

मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट का शीर्षक : "शिफ्टिंग पैराडाइम्स: यूनाइटेड टू डिलीवर"
- रिपोर्ट : संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र की संरचना, उसकी संस्थाओं के सहयोग करने के तरीके और उसके संचालन में आमूलचूल परिवर्तन के प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

--:17:--

UN ने निम्न तीन स्तंभों में कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पेश किए :



- **उद्देश्य :** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करने के तरीकों पर सदस्य देशों के विचार-विमर्श को सूचित करना तथा सभी सुधार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सहित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार करना।
- यह रिपोर्ट कार्यों में आपसी तालमेल, कार्यों के कम दोहराव और अधिक प्रभावी सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है।

इस रिपोर्ट में मुख्य क्षेत्रों के लिए किए गए प्रस्ताव :

प्रस्ताव	विवरण
शांति एवं सुरक्षा	इसमें कार्यालयों एवं नेतृत्व स्तरों को एकीकृत करना; शांति की स्थापना एवं महिलाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना आदि शामिल हैं।
मानवाधिकार	मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में समाहित करने के लिए एक समग्र मानवाधिकार समूह बनाना, जिसका नेतृत्व उच्चायुक्त करेगा।

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



संघारणीय विकास	UN एजेंसियों (UNDP व UNOPS, UNFPA एवं UN वीमेन) के विलय का आकलन करने; 2026 तक UNAIDS को समाप्त करने, और विशेषज्ञ कार्यबल के लिए संयुक्त ज्ञान केंद्र बनाने की सिफारिश की गई है।
मानवीय सहायता	ब्यूरोक्रेसी में कटौती के लिए एक नया मानवतावादी सहायता समझौता (New Humanitarian Compact) किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में व्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों का समन्वय करने के लिए एक प्रणाली-व्यापी मानवाधिकार समूह की स्थापना करना।
प्रौद्योगिकी एवं डेटा	'UN सिस्टम डेटा कॉमन्स' और एक 'टेक्नोलॉजी एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म' का प्रस्ताव किया गया है, ताकि संचालन को आधुनिक बनाया जा सके तथा डेटा को एकीकृत किया जा सके।
वित्त-पोषण	सामूहिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन जुटाना एवं वित्त-पोषण के मुख्य तंत्र में सुधार करना। नौकरशाही में कटौती और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अरबों डॉलर के निवेश को एकीकृत करने के लिए एक नए मानवीय समझौते की शुरुआत करना।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

UN80 पहल :

- UN80 पहल संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने की योजना है।
- उद्देश्य : संगठन को अधिक प्रभावी व दक्ष बनाना, संचालन को व्यवस्थित करना और बदलती दुनिया के लिए प्रासंगिक बनाना।

--:19:--

इसे तीन वर्कस्ट्रीम में बांटा गया है:

- पहला**
 - आंतरिक दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार पर केंद्रित।
- दूसरा**
 - संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कार्यों को निर्धारित करने वाले शासनादेश दस्तावेजों की जाँच और समीक्षा करना।
- तीसरा**
 - संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव और कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करना।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- **स्थापना** : वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा।
- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- **UNSC में सदस्यों की संख्या 15** : 5 स्थायी सदस्य (P5) + 10 गैर-स्थायी सदस्य (2 वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।)
- **5 स्थायी सदस्य** : संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
- भारत ने UNSC में 8 बार गैर-स्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है।

सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता

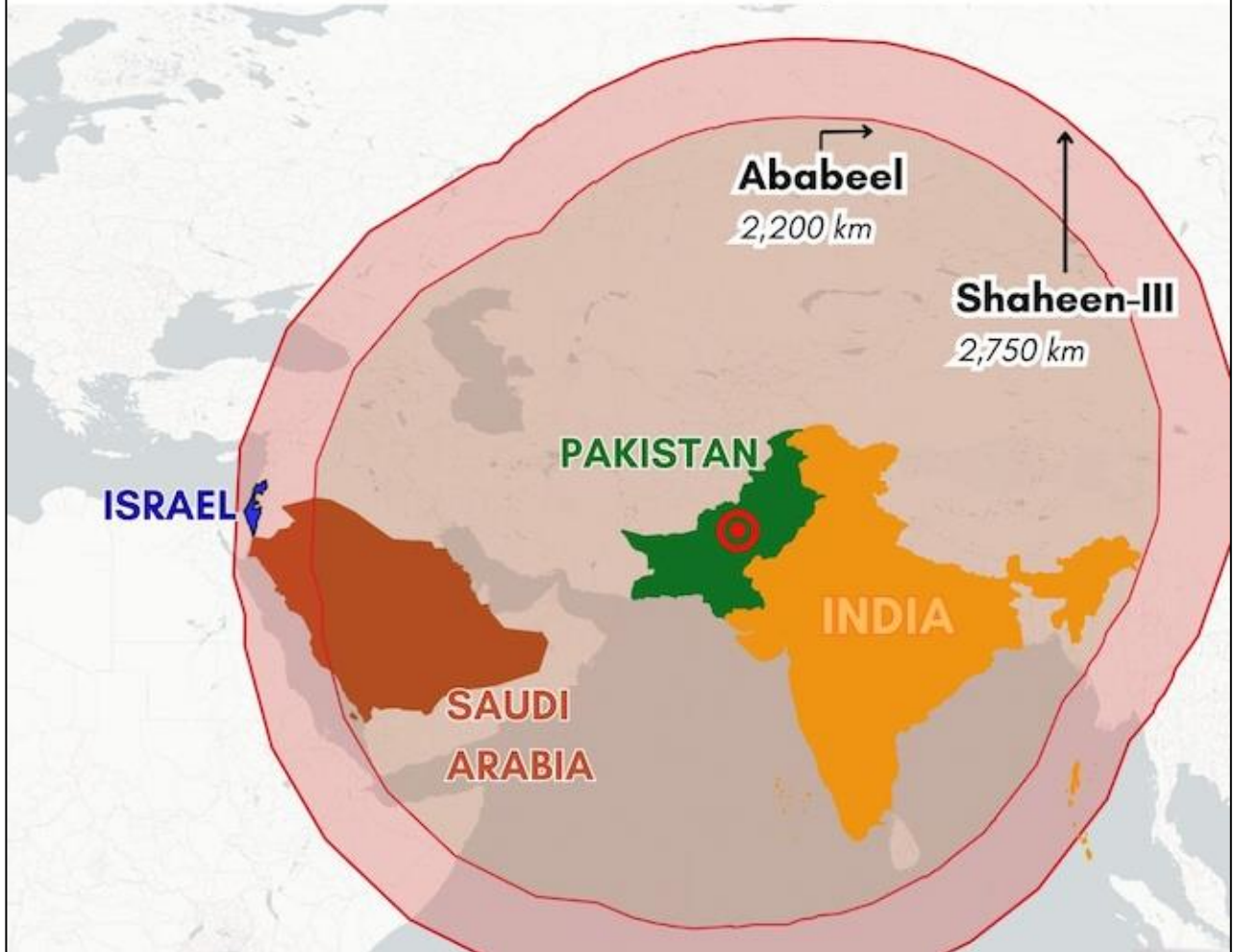
चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 'सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य:** दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना तथा किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है।
- समझौते के अनुसार दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।

Reach of Pakistan's Nuclear Capable Missiles



प्रभाव:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** सऊदी अरब के लिए यह ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल से संबंधित खतरों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है।
- **परमाणु युद्ध:** समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को अपनी परमाणु सुरक्षा देना भी शामिल है, परमाणु युद्ध की चिंताओं को और बढ़ाता है।
- **रणनीतिक बदलाव:** यह क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कम करता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोगी इजरायल गाजा और अन्य क्षेत्रीय पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है।
 - इससे क्षेत्र में उत्पन्न रणनीतिक शून्य का फायदा चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है।
- **भारत के लिए निहितार्थ:** सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के आलोक में पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में भारत के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में सामरिक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

- दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को 2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।
- **आर्थिक:** भारत, सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
 - 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन था और भारत निवल आयातक बना रहा।
 - 2024 में भारत में आने वाले कुल विप्रेषण (रेमिटेंस) में लगभग 6.7% सऊदी अरब से आया था।
- **ऊर्जा साझेदारी:** सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है।

चाबहार बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह को दी गई 'प्रतिबंधों से छूट' वापस लेने की घोषणा की।

मुख्य बिन्दु:

- अमेरिका ने 2018 में ईरान पर लगे प्रतिबंधों से चाबहार बंदरगाह परियोजना को छूट दी थी।

BRIDGING THE GAP

Indian presence in Chabahar is expected to offset Chinese presence in Pakistani port of Gwadar

➔ **COST CUTTER** The port will be used to ship crude oil and urea, greatly reducing India's transportation costs

➔ **AFGHAN CONNECT** A railway line, to be built by Iacon International, will connect Chabahar port to Zahedan on Afghan border

➔ **BIGGER LINK** The port will link to International North-South Transport Corridor that will connect India with Azerbaijan, Turkmenistan and other Central Asian trading partners



Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



चाबहार बंदरगाह:

- यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक डीप वाटर पोर्ट है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- यह भारत के सबसे निकटतम ईरानी बंदरगाह है। यह भारत को पाकिस्तान जाए बिना स्थल-रुद्ध अफगानिस्तान तथा अन्य मध्य एशियाई देशों तक पहुँच प्रदान करता है।
- 2024 में, भारत ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को 10 साल के लिए इस बंदरगाह को विकसित करने और संचालित करने का अधिकार दिया।
- इसके अलावा, यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) का भी हिस्सा है। यह गलियारा भारत को यूरोप, रूस, मध्य एशिया आदि से जोड़ता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:24:--

हाई सीज ट्रीटी (खुले समुद्र पर संधि)

चर्चा में क्यों?

- 60वें (60 देशों) अनुसमर्थन के साथ हाई सीज ट्रीटी (खुले समुद्र पर संधि) के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुख्य बिन्दु:

- हाई सीज ट्रीटी को 2023 में "राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) पर अंतर-सरकारी सम्मेलन" द्वारा अपनाया गया था।

हाई सीज ट्रीटी:

- **औपचारिक नाम:** 'राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता' (BBNJ समझौता) है।

- यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।

- इसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के समझौते के तहत अपनाया गया है।

- यह UNCLOS का तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। इसके अलावा, अन्य दो समझौते 1994 में UNCLOS के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता और 1995 का संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता हैं।

- **हाई सीज/ खुला समुद्र:** यह वह समुद्री क्षेत्र है, जो किसी भी देश के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होता है। यह वैश्विक साझा क्षेत्र है, जिसका सभी देश वैध अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे- नौवहन, हवाई उड़ान, समुद्र के नीचे केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

भारत और हाई सीज ट्रीटी

- 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की थी।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

H-1B वीजा

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने वाले प्रावधान पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

H-1B वीजा:

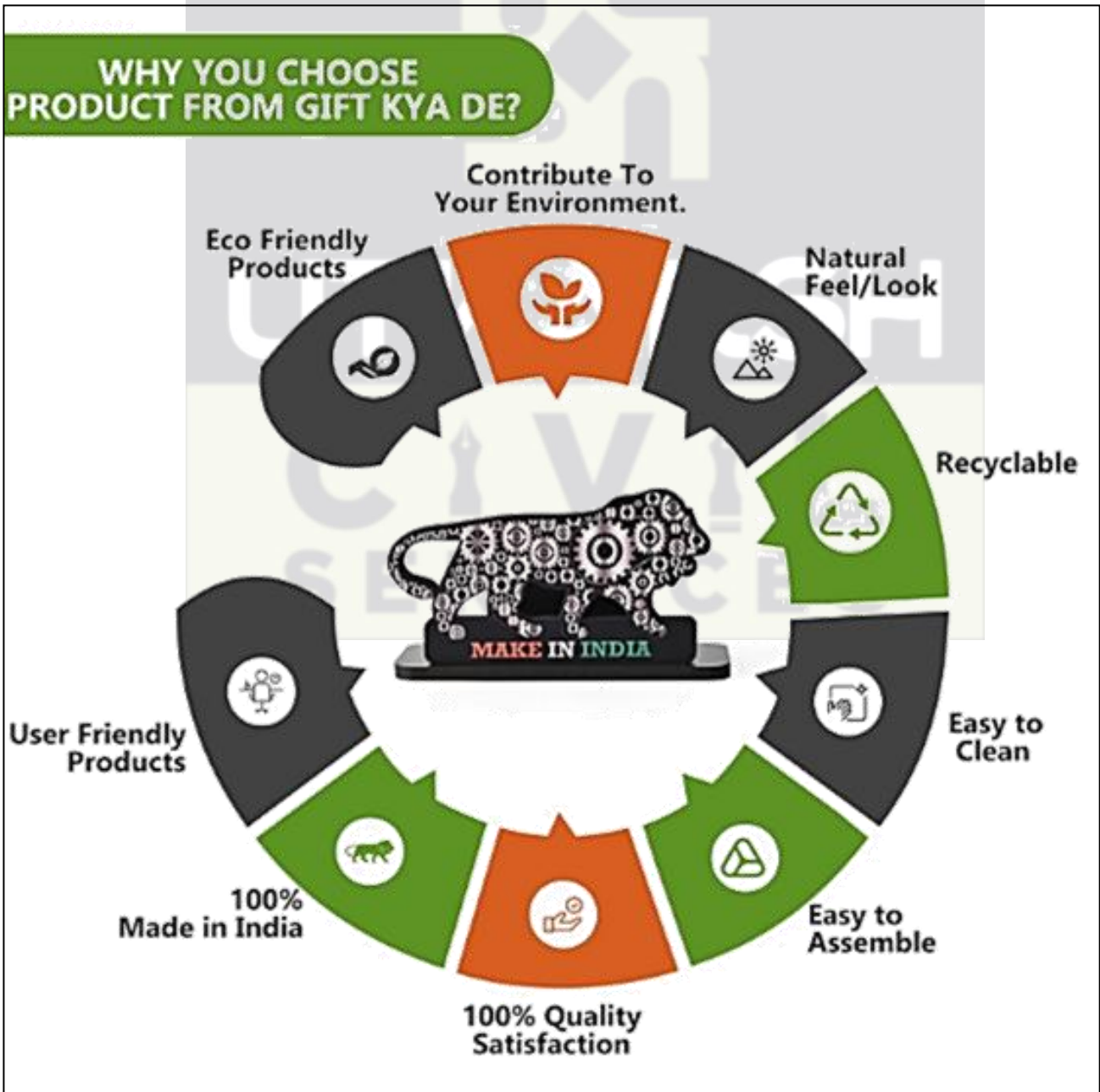
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका का गैर-आप्रवासी वीजा है, जो कुशल कामगारों को अस्थायी रूप से कार्य करने की अनुमति देता है।
- इनमें आमतौर पर IT, इंजीनियरिंग, और चिकित्सा पेशा शामिल हैं। इनके लिए स्नातक डिग्री या इसके बराबर के अनुभव की आवश्यकता होती है।
- **स्पोसरशिप:** इस वीजा के लिए नियोक्ता (कंपनियों) का स्पोसरशिप अनिवार्य है।
- **वैधता:** यह शुरुआत में 3 साल के लिए वैध होता है। हालांकि इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- **वार्षिक सीमा:** हर साल 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं, और एडवांस्ड-डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा उपलब्ध होते हैं।

महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

मेक इन इंडिया को दशक पूर्ण

चर्चा में क्यों?

- 20 सितम्बर, 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा मेक इन इंडिया पहल के एक दशक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेक इन इंडिया स्मारक सिक्का जारी किया।



मुख्य बिन्दु:

योजना की उपलब्धियाँ:

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :** वर्ष 2014 और 2024 के बीच, भारत को 667 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो उदारीकरण के बाद से अब तक हुए सभी निवेशों का लगभग दो-तिहाई है।
- कारोबार सुगमता :** देश ने कारोबार सुगमता के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जो वर्ष 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गया है।
- व्यापारिक निर्यात :** वित्त वर्ष 2024-25 में व्यापारिक निर्यात 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित हो गया।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम :** भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम 1.80 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप तक बढ़ गया है, जिससे यह अमरीका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा है।
- Note:** वर्ष 2025 तक 118 यूनिर्कॉर्न के साथ 17.6 लाख से अधिक नौकरियाँ सर्जित की हैं।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना :** 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना ने लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।

7. **भारत की औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार :**
8. **भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जो 99 प्रतिशत स्मार्टफोन का घरेलू उत्पादन करता है।**
9. **रक्षा निर्यात:** धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन, हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस, कई पनडुब्बियाँ जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं और कई देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है।
10. **उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता :** इसके परिणामस्वरूप, 2015 से वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) में भारत की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्तमान में इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। यह सुधार भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को दर्शाता है।
11. **भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा :** वर्तमान में, एशियाई देशों में भारत में कर की दरें सबसे कम हैं। इस वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक आकर्षण क्षमता बढ़ गई है।
12. **संधारणीय विकास की ओर कदम :** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा, इससे प्राकृतिक गैस और अमोनिया के आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे 1 लाख करोड़ रुपये की भी बचत होगी।

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

मेक इन इंडिया पहल :

- **शुभारंभ :** 25 सितम्बर, 2014
- **उद्देश्य :** भारत को विनिर्माण, विदेशी निवेश, डिजाइन व नवाचार के लिए एक वैश्विक केन्द्र में परिवर्तित करना।

अन्य उद्देश्य:

1. भारतीय उद्योग की संवृद्धि दर को बढ़ाकर प्रति वर्ष 12-14 प्रतिशत तक करना।
 2. 2022 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 100 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करना।
 3. 2022 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना। अब इसे संशोधित करके 2025 तक कर दिया गया है।
- **धेय :** 'वोकल फॉर लोकल'।

"मेक इन इंडिया" के स्तंभ:

1. **नई प्रक्रियाएँ :** इसके तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस को सबसे महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में मान्यता दी गई है।
2. **नई अवसंरचना :** इसमें औद्योगिक गलियारा और स्मार्ट शहरों का विकास तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उच्च-गति वाली संचार सुविधाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है।
3. **नए क्षेत्रक :** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण और रेलवे अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
4. **नई मानसिकता :** सरकार की भूमिका विनियामक के बदले सुविधाप्रदाता के रूप में तय की गई है।

--:30:--

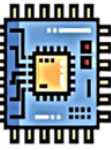
'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें



उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं: भारत की विनिर्माण क्षमताओं और भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ PLI योजनाओं की घोषणा की गई है।



पी.एम. गतिशक्ति: मल्टीमॉडल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 2025 तक आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना।



सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास: एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (2021) को मंजूरी दी गई है।



राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022): एडवांस प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर एकीकृत, दक्ष और सतत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।



स्टार्ट-अप इंडिया: इसे उद्यमियों की सहायता करने, एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाने और भारत को रोजगार के अवसर सृजन करने वाले देश में बदलने के लिए आरंभ किया गया है।



कर सुधार: GST लागू होने से देश की कर संरचना एकीकृत हुई है, उत्पादन लागत में कमी आई है और समग्र दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है।



यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI): भारत का UPI डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व में अग्रणी सिस्टम के रूप में उभरा है। इसकी वजह से विश्व स्तर पर होने वाले रियल टाइम भुगतान या लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी 46% है।



राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम: इसके तहत 11 अनुमोदित औद्योगिक गलियारों में 32 परियोजनाओं के जरिए प्रतिस्पर्धी ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों और नोड्स का विकास किया जाना है।

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



मेक इन इंडिया 2.0 :

- **शुरुआत** : वर्ष 2021
- **क्षेत्रक** : 27 क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है।
- **लागू** : विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के तत्वावधान में लागू किया जा रहा है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है, जबकि वाणिज्य विभाग सेवा क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है



--:32:--

प्रोजेक्ट स्वायत्त



मुख्य बिन्दु:

- यह परियोजना इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के नेतृत्व में और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है।
- प्रोजेक्ट स्वायत्त का उद्देश्य भारत का पहला मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप विकसित करना है।
- **मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप्स (MASS)**
- ये ऐसे पोत होते हैं जो बहुत हद तक व्यक्ति द्वारा संचालित न होकर स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।

UTKARSH

CIVIL SERVICES

ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर



मुख्य बिन्दु:

- भारत ने देश में ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

FAO की ब्लू पोर्ट्स पहल के बारे में

- 'ब्लू पोर्ट्स पहल' सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए समुद्री और तटीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय क्षेत्रों में बदलने को बढ़ावा देती है।
- इसका उद्देश्य फिशिंग हार्बर को स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतिक केंद्र बनने में मदद करना है।

इंडिया AI मिशन



मुख्य बिन्दु:

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने घोषणा की है कि इंडिया AI मिशन के तहत देशभर में 500 डेटा लैब स्थापित किए जाएंगे।

इंडिया AI मिशन:

- **शुरुआत:** इसे 2024 में MeitY ने लॉन्च किया था।
- **लक्ष्य:** कंप्यूटिंग तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करके, डेटा की गुणवत्ता बढ़ाकर, और स्वदेशी AI क्षमताओं को विकसित करके AI इनोवेशन को बढ़ावा देना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इंडियाAI, जो MeitY के तहत एक स्वायत्त व्यावसायिक प्रभाग है।

UTKARSH

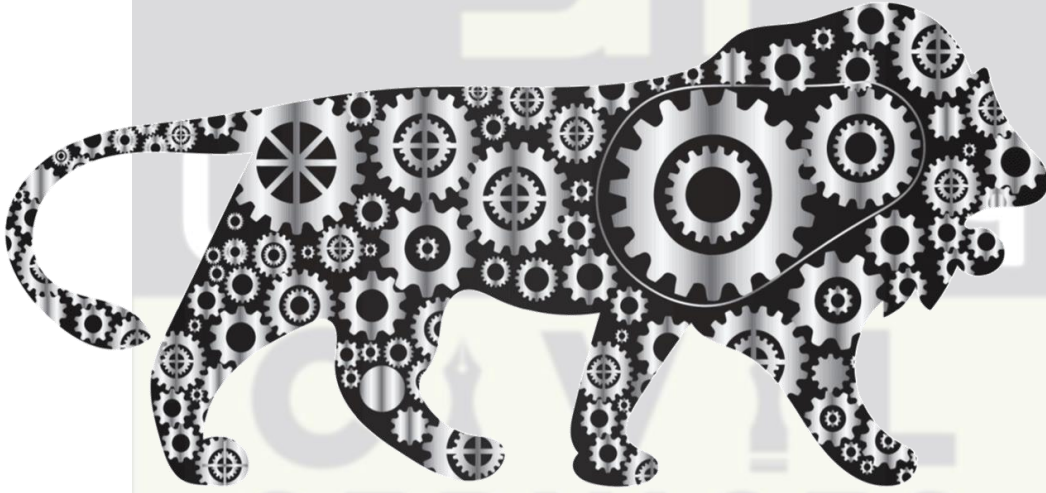
CIVIL SERVICES

आर्थिक परिदृश्य

भारत का लॉजिस्टिक्स लागत तंत्र

चर्चा में क्यों?

- 20 सितम्बर, 2025 को नई दिल्ली में "मेक इन इंडिया" के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य पर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के आकलन पर रिपोर्ट जारी की।



MAKE IN INDIA

मुख्य बिन्दु:

- NCAER की ओर से DPIIT के लिए तैयार किए गए वर्तमान आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कुल GDP का लगभग 7.97 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- पहली बार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत का एक व्यापक और वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त किया गया अनुमान होगा, जिसमें द्वितीयक आँकड़ों को राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों के साथ मिलाकर एक मिश्रित पद्धति का उपयोग किया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



- यह पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) के उस आदेश का अनुसरण करती है, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स लागतों को मापने और उन्हें वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करने हेतु एक समान ढाँचा स्थापित किया जाना है।
- यह रिपोर्ट कई परिवहन साधनों, उत्पाद श्रेणियों और फर्म आकारों में लॉजिस्टिक्स लागतों को शामिल करके एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।
- गत पाँच वर्ष के अनुमान से ज्ञात होता है कि गैर-सेवा उत्पादन की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत की बढ़ती दर धीरे-धीरे धीमी हो रही है।
- इस सुधार का श्रेय प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल ढुलाई गलियारे, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, एकीकृत चेक पोस्ट, एकीकृत रसद इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) का विकास और रसद दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (लीप) जैसी पहलों को दिया जा सकता है।

-:37:-

सैन्य अभ्यास

भारत और ग्रीस के मध्य पहला द्विपक्षीय अभ्यास

चर्चा में क्यों?

- 18 सितंबर, 2025 को भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला आयोजन भूमध्य सागर में संपन्न हुआ।



मुख्य बिन्दु:

यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया:

पहला बंदरगाह चरण : 13 से 17 सितंबर, 2025 तक
सलामीस नौसेना बेस पर।

दूसरा समुद्री चरण : 17 और 18 सितंबर, 2025

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



- भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद ने किया।
- **बंदरगाह चरण** : दोनों नौसेनाओं के कर्मियों ने आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रॉस-डेक दौरे, चालक दल के मध्य पेशेवर बातचीत और हेलेनिक नौसेना के एली क्लास फ्रिगेट एचएस थेमिस्टोकल्स पर आयोजित प्री-सेल सम्मेलन शामिल थे।
- **समुद्री चरण** : दोनों नौसेनाओं की इकाइयों के बीच जटिल समुद्री युद्धाभ्यास और सामरिक अभ्यास हुए, जिनमें वीबीएसएस ऑपरेशन, समुद्र में पुनःपूर्ति प्रक्रियाएँ, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध, समन्वित गन फायरिंग और क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शामिल थे, जिससे अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि हुई।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:39:--

पुरस्कार

दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2023

चर्चा में क्यों?

- दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार द्वारा मोहनलाल विश्वनाथन नायर को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- जिसका आधिकारिक समारोह 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान आयोजित किया जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

- शुरुआत : वर्ष 1969
- पुरस्कार की घोषणा : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा।
- पुरस्कार : एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और ₹1,000,000 (US\$13,000) की नकद राशि।

--:40:--

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. मिथुन चक्रवर्ती
2. शंकर महादेवन
3. आशुतोष गोवारिकर

वर्ष 2023 के लिए ; मोहनलाल विश्वनाथन नायर :

- **सम्बन्ध** : केरल
- मोहनलाल ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया है।
- वर्ष 1980 के दशक में 'मंजिल विरिंजा पूक्कल' से करियर की शुरुआत करने वाले मोहनलाल ने लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है।
- **पुरस्कार** : मोहनलाल को भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2019 में पद्मभूषण से भी सम्मानित किया तथा वर्ष 2009 में भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया था।

मोहनलाल विश्वनाथन नायर द्वारा अभिनय फिल्मों को नेशनल अवॉर्ड :

वर्ष	फिल्म
1989	किरीदम (स्पेशल मेंशन)
1991	भारतम (बेस्ट एक्टर)
1999	वानप्रस्थम (बेस्ट एक्टर) ; कान्स अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित
2016	जनता गैराज (स्पेशल जूरी अवॉर्ड)
2016	मुन्थिरिवल्लिकल (स्पेशल जूरी अवॉर्ड)

--:41:--

Daily Current Affairs

Date : 22 September, 2025



अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

दादा साहब फाल्के:

- वर्ष 1913 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने पहली भारतीय फुल-लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की।
- वर्ष 1969 में राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेताओं की सूची :

समारोह वर्ष	प्राप्तकर्ता
2025 (75वाँ)	मोहनलाल (मलयालम)
2024 (74वाँ)	मिथुन चक्रवर्ती
2023 (73वाँ)	रेखा
2022 (72वाँ)	आशा पारेख
2021 (71वाँ)	रजनीकांत

-:42:-